हिन्दी साप्ताहिक

PRGI No:- UABIL/25/A3383

उत्तराखण्ड अभ्युदय

♦वर्ष -02 ♦ अंक-36 ♦देहरादून - रविवार 12 जुलाई 2026 ♦पृष्ठ : 4 ♦मूल्यः 1/-15

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से रेल परियोजनाओं एवं कनेक्टिविटी विस्तार पर की चर्चा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राज्य में रेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण, रेल संपर्क

के विस्तार तथा राज्य की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, धार्मिक एवं पर्यटन महत्व तथा जनहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रस्ताव केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष रखे।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से देश के प्रमुख राज्यों में से एक है। चारधाम यात्रा, हरिद्वार एवं ऋषिकेश के धार्मिक स्थलों, योग एवं आध्यात्मिक पर्यटन तथा आगामी कुम्भ-2027 के आयोजन के दृष्टिगत प्रतिवर्ष देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु एवं पर्यटक राज्य में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती यात्री संख्या एवं पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए राज्य में आधुनिक, सुदृढ़ एवं सुविधाजनक रेल नेटवर्क का विस्तार समय की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री को अवगत कराया कि महाराष्ट्र, विशेषकर मुम्बई में बड़ी संख्या में उत्तराखण्ड मूल के नागरिक निवास करते हैं, जिनका अपने गृह राज्य से निरंतर आवागमन बना रहता है। इसके साथ ही चारधाम, बाबा नीम करौली धाम (श्री कैंची धाम), जागेश्वर धाम सहित राज्य के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों में वर्षभर देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है। वर्तमान में मुम्बई से हरिद्वार एवं रामनगर के लिए संचालित रेल सेवाओं की संख्या एवं आवृत्ति यात्रियों की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, जिससे यात्रा सीजन, चारधाम यात्रा, अवकाश एवं त्योहारों के दौरान यात्रियों को आरक्षण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मुम्बई-देहरादून के मध्य वन्दे भारत अथवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस सेवा प्रारम्भ करने तथा मुम्बई-हरिद्वार एवं मुम्बई-रामनगर रेल सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे यात्रियों, प्रवासी उत्तराखण्डवासियों एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी तथा राज्य में पर्यटन, व्यापार एवं निवेश को नई गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने मुम्बई-देहरादून के मध्य वन्दे भारत अथवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस सेवा प्रारम्भ करने तथा मुम्बई-हरिद्वार एवं मुम्बई-रामनगर रेल सेवाओं की आवृत्ति बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन रेल सेवाओं के विस्तार से यात्रियों, प्रवासी उत्तराखण्डवासियों, श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्राप्त होगी तथा राज्य में पर्यटन, व्यापार एवं निवेश को भी नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने देहरादून-कोटा रेल सेवा को सूरत-वड़ोदरा-मुम्बई तक विस्तारित करने तथा रामनगर-मुम्बई एवं हरिद्वार-मुम्बई रेल सेवाओं को नियमित अथवा सप्ताह में कम से कम तीन दिन संचालित किए जाने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन को बंद कर उसकी भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (न्प्क्ठ), उत्तराखण्ड सरकार एवं रेल भूमि विकास प्राधिकरण (त्स्क।), रेल मंत्रालय के मध्य एसेट मॉनेटाइजेशन एवं ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर की समग्र मास्टर प्लानिंग के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में त्स्क। को आवश्यक औपचारिक निर्देश प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया।

मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रमुख रेल परियोजनाओं के संबंध में किच्छा-सितारगंज-खटीमा नई रेल लाइन परियोजना की सम्पूर्ण लागत भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने, सर्वेक्षण कार्य से संबंधित स्थानीय किसानों की चिंताओं का समाधान किए जाने तथा ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत शीघ्र रेल संचालन प्रारम्भ करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग आजीविका एवं अन्य कारणों से मुम्बई सहित देश के विभिन्न स्थानों में निवास करते हैं। वहीं चारधाम, बाबा नीम करौली धाम (श्री कैंची धाम), जागेश्वर धाम सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों में वर्षभर श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। राज्य के कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशन रामनगर, देहरादून एवं हरिद्वार हैं, जहां से पर्वतीय क्षेत्रों के यात्रियों को रेल सुविधा उपलब्ध होती है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेल सेवाओं के विस्तार की आवश्यकता पर मुख्यमंत्री ने विशेष बल दिया।

मुख्यमंत्री ने टनकपुर से संचालित त्रिवेणी एक्सप्रेस, मथुरा एक्सप्रेस एवं दौराई एक्सप्रेस के यात्रा मार्ग में पड़ने वाले बनबसा रेलवे स्टेशन पर अल्प समय के ठहराव की व्यवस्था किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि बनबसा भारत-नेपाल सीमा से लगा हुआ व्यापारिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा यहां भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट की यूनिट भी स्थापित है। बनबसा स्टेशन पर ठहराव से स्थानीय नागरिकों, यात्रियों एवं सेना को बेहतर परिवहन सुविधा प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय रेल मंत्री ने बनबसा स्टेशन पर उक्त रेल सेवाओं के अल्प ठहराव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण के अंतर्गत रायवाला से देहरादून तक लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण करने तथा हरिद्वार, हर्रावाला, देहरादून, खटीमा, लक्सर, रुड़की, टनकपुर एवं बनबसा रेलवे स्टेशनों के सौन्दर्यीकरण एवं विस्तारीकरण का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय रेल मंत्री ने उक्त प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने खटीमा-मझोला पीलीभीत के मध्य रेलवे फाटक संख्या-18ब को जनहित में पुनः खोले जाने का अनुरोध भी केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि रेलवे फाटक बंद होने से स्थानीय ग्रामीणों, कृषकों एवं पर्यटकों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित कोकोडायल पार्क में आने वाले पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए रेलवे फाटक का संचालन पुनः प्रारम्भ किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय रेल मंत्री ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक सहमति प्रदान कर दी है।केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।

भारी बारिश के बीच ग्राउंड जीरो पर उतरे डीएम

देहरादून। मौसम विभाग के रेड अलर्ट और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच जिला प्रशासन अलर्ट है। भारी बारिश के बीच खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने विभागों के अधिकारियों को आपदा प्रभावित इलाकों में हरसंभव सहायता पहुंचाने की हिदायत दी। सहस्रधारा-सरोना मोटर मार्ग का स्थाई ट्रीटमेंट नहीं होने पर नाराजगी जताई।

डीएम ने गुरुवार को भारी बारिश के बीच सहस्रधारा, कार्लीगाढ़ और अति-संवेदनशील सपेरा बस्ती का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से बात कर उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और अधिकारियों को तत्परता से काम करने के सख्त निर्देश दिए। डीएम सबसे पहले सहस्रधारा-सरोना मोटर मार्ग पहुंचे, जो बरसात के कारण आए मलबे की वजह से चार अलग-अलग स्थानों पर पूरी तरह ठप हो गया है। पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता ने मौके पर बताया कि पिछली आपदा में यह मार्ग 11 से अधिक जगहों पर टूटा था, जिसे अस्थाई रूप से खोला गया था। बजट की कमी और स्थाई ट्रीटमेंट न होने के कारण हल्की बारिश में भी यह बार-बार बंद हो जाता है।

डीएम ने पीएमजीएसवाई को दोनों तरफ से जेसीबी मशीनें लगाकर मलबा साफ करने और मार्ग को तुरंत सुचारू करने को कहा। डीएम ने कहा कि मार्ग के स्थाई ट्रीटमेंट और प्रोटेक्शन कार्यों के लिए वे खुद शासन स्तर पर वार्ता करेंगे। निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग ने बताया कि कार्लीगाढ़ में पिछली आपदा के मलबे का निस्तारण, समतलीकरण और नदी चौनलाइजेशन का काम पूरा कर लिया गया है। डीएम ने तहसील प्रशासन को निर्देश दिए कि नदी पार रहने वाले सभी परिवारों के पास पर्याप्त खाद्य सामग्री, बिजली और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, इन सभी परिवारों के फोन नंबर जिला कंट्रोल रूम में दर्ज किए जाएं।

जिले में 14 ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध

जिलाधिकारी ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सपेरा बस्ती में सुरक्षात्मक कार्यों को तुरंत पूरा करें। जिन लोगों के मकान असुरक्षित हैं, उन्हें फौरन सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाए।

गल्जवाड़ी ग्रामप्रधान चुनाव विवाद में ने एसडीएम का आदेश निरस्त, दोबारा सुनवाई होगी

देहरादून। जिला अदालत ने ग्राम पंचायत गल्जवाड़ी की महिला ग्राम प्रधान के निर्वाचन से जुड़े विवाद में एसडीएम कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया गया। जिला जज हरीश कुमार गोयल की अदालत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का हवाला देते हुए मामले को दोबारा नए सिरे से सुनवाई और फैसले के लिए एसडीएम कोर्ट को वापस भेज दिया है।हरिकाला गल्जवाड़ी की ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। उनके इस निर्वाचन को पराजित प्रत्याशी लीला शर्मा ने एक चुनाव याचिका के जरिए चुनौती दी थी। आरोप लगाया गया था कि हरिकाला पुन ने वन भूमि पर अवैध कब्जा कर आवासीय मकान बनाया है।

इसलिए उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत वे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थीं और उनका नामांकन रद्द किया जाना चाहिए था। इस पर सुनवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट ने 25 मार्च 2026 को प्रधान के खिलाफ आदेश पारित किया था। इस आदेश के खिलाफ हरिकाला ने जिला जज की अदालत में सिविल रिवीजन याचिका दायर की थी। मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद जिला जज हरीश कुमार गोयल ने अपने निर्णय में एसडीएम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और मुख्य रूप से दो कारणों से आदेश को रद्द कर दिया। जिला अदालत ने पाया कि एसडीएम का आदेश पूरी तरह से तहसीलदार (सदर) की 11 मार्च 2026 की एक रिपोर्ट पर आधारित था।

सम्पादकीय

हरियाली का लोकपर्व; "हरेला"

हरेलोत्सवः सदा शोभनोऽयं,
संस्कृतिं प्रकृतिं च संयोजयन्।
वृक्षारोपणं धर्म एव नित्यं,
पर्यावरणं रक्षिता वयं स्यात्।।

अर्थात

पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण को समर्पित,हरेला केवल एक पर्व नहीं, बल्कि संस्कृति, प्रकृति और चेतना से जुड़ा एक गहरा भाव है। अतीत से यह हमें पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाता है।

लोकपर्व हरेला के पावन अवसर पर राज्य भर में उद्यान विभाग द्वारा 11लाख फलदार व सगंध एवं औषधीय पौधे के रोपण का लक्ष्य घोषित किया गया है।पर्यावरण संरक्षण के भाव जगाने वाला ष्हरेलाष्, केवल एक लोकपर्व नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, प्रकृति और चेतना से जुड़ा एक गहरा भाव है, जो हमें पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाता है।

उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से समृद्ध राज्य है,जिसकी रक्षा करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है।पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से संचालित हो रहे 'पंचामृत संकल्प', 'नेट जीरो इमिशन', 'लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' और 'एक पेड़ माँ के नाम' जैसे अभियान बेहद महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए 'स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी (SARRA)' का गठन किया गया है। इसके माध्यम से अब तक 6,500 से अधिक जल स्रोतों का संरक्षण और 3.12 मिलियन घन मीटर वर्षा जल का संचयन किया गया है। राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है और वाहनों में कूड़ेदान अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तराखंड में श्रावण मास में हरेला पूजन के उपरांत वृक्षारोपण करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो हमारी सांस्कृतिक चेतना और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रमाण है। हरेला पर्व हमें यह सिखाता है कि प्रकृति की रक्षा करना केवल दायित्व नहीं, बल्कि एक पुनीत कर्तव्य है। देवभूमि उत्तराखंड की चतुर्दिक प्रगति हो, हर तरफ खुशियां हों ,प्रकृति में हर तरफ हरियाली हो,हरतरफ खुशहाली हो,यही ईश्वर से कामना है। उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के उद्देश्य से परिपूरित, प्रतिपल हमारे प्रयास अहर्निश जारी रहेंगे।।

जय देवभूमि उत्तराखण्ड!!जय भारत !!

डॉ.गार्गी मिश्रा

कॉमन एंट्रेस टेस्ट के खतरे

नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नात्तक कक्षाओं में दाखिले के लिए एक साझा दाखिला परीक्षा कराने का ऐलान किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट यानी सीयूईटी 2022 की आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा का फॉर्मेट आदि जारी कर दिया है। पहली नजर में देखने पर ऐसा लग रहा है कि यह बहुत अच्छी पहल है क्योंकि इससे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले की चाहत रखने वाले सभी छात्रों को बराबरी का मैदान मिलेगा। यह इसलिए जरूरी लग रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से कई राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में और केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की परीक्षाओं में भी 99 और सौ फीसदी अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय सहित कई और विश्वविद्यालयों में दाखिले का कटआ. ँफ सौ फीसदी तक जा रहा है।

यूजीसी के इस फैसले की मोटे तौर पर वाहवाही ही हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इससे 12वीं पास करके उच्च शिक्षा हासिल करने की चाहत रखने वाले छात्रों की सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह जेईई की परीक्षा के जरिए इंजीनयरिंग और नीट की परीक्षा के जरिए मेडिकल में दाखिले की व्यवस्था छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं करती हैं वैसे ही यह एंट्रेस टेस्ट भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। उलटे इससे कुछ नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे नीट की परीक्षा के कारण तमिलनाडु में पैदा हुई है। बहरहाल, सबसे पहली बात तो यह है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए परीक्षा की व्यवस्था शुरू होने से 12वीं के अंकों का महत्व खत्म हो जाएगा। दाखिला परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अंक हासिल करने की एक अर्हता रखी जाएगी, उसके अलावा इन अंकों का कोई महत्व नहीं होगा।

इसका पहला असर तो यह होगा कि पढ़ाई का पूरा पैटर्न बदल जाएगा। बोर्ड की परीक्षा के लिए अभी छात्र समग्रता में पढ़ाई करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि इस अंक के आधार पर उनको अच्छे विश्वविद्यालय और मनपसंद कोर्स में दाखिला मिलेगा। अगर अच्छे विश्वविद्यालय और मनपसंद कोर्स के लिए 12वीं के अंकों का महत्व खत्म हो जाएगा तब छात्र क्लासरूम की पढ़ाई पर कम ध्यान देंगे। फिर उनकी पढ़ाई सीधे दाखिला परीक्षा की तैयारियों पर केंद्रित हो जाएगी। जाहिर है यह पढ़ाई क्लासरूम में नहीं होगी। जिस तरह इंजीनियरिंग और मेडिकल में दाखिले की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उगे हैं उसी तरह केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले की परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान भी पैदा होंगे। यहीं से गैरख़ बराबरी वाली व्यवस्था शुरू हो जाएगी।

दाखिले के लिए परीक्षा आयोजित करने के पक्ष में यह दलील दी जा रही है कि इससे सभी छात्रों को बराबरी का मैदान मिलेगा लेकिन असल में यह अधूरी दलील है। एक तरफ वे छात्र होंगे, जो महंगे कोचिंग में जाकर या महंगे शिक्षक से पढ़ाई करके दाखिला परीक्षा की तैयारी करेंगे और दूसरी ओर वे छात्र होंगे, जो क्लासरूम की पढ़ाई के आधार पर दाखिला परीक्षा में बैठेंगे। दोनों के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक उसी तरह जैसे जेईई और नीट की परीक्षा में होता है। दिल्ली से लेकर कोटा तक फैले कोचिंग संस्थानों से पढ़ाई करके इंजीनियरिंग, मेडिकल की दाखिला परीक्षा में बैठने वालों का बाकी छात्रों से कोई मुकाबला नहीं रह जाता है। इसी वजह से तमिलनाडु सरकार नीट का विरोध कर रही है क्योंकि वहां 12वीं के अंकों के आधार पर गरीब से गरीब छात्र को भी सरकारी मेडि. कल कॉलेज में दाखिला मिलता है। इसलिए स्नात्तक कक्षाओं में अंक की बजाय एंट्रेस टेस्ट के आधार पर दाखिले की व्यवस्था एक किस्म की गैर बराबरी को खत्म करके उससे बड़ी दूसरे किस्म की गैर बराबरी की व्यवस्था बनाने वाली साबित होगी।

दाखिले के लिए एक परीक्षा कराने के फैसले की दूसरी कमी यह है कि इसके आधार किसी छात्र का समग्रता में मूल्यांकन नहीं किया जा सकेगा। ध्यान रहे 12वीं की परीक्षा में मिला अंक किसी एक परीक्षा का नतीजा नहीं होता है। वह 12वीं तक की पूरी पढ़ाई का प्रतिबिंब होता है। छात्र कई तरह की लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और व्यक्तित्व के विकास के दौर से गुजर कर 12वीं पास करता है। इसलिए 12वीं की परीक्षा में मिले अंक एक छात्र के समग्र मूल्यांकन का आधार बनाते हैं। इसके उलट दाखिला परीक्षा किसी छात्र के ओवरऑल मूल्यांकन का आधार नहीं बन सकती है। हो सकता है कि 12वीं तक की पढ़ाई बहुत अच्छे से करने वाला छात्र दाखिला परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाए और उसे किसी अच्छे विश्विद्यालय में दाखिला नहीं मिले। यह उसके साथ अन्याय होगा। सोचें, इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए अब दो बार जेईई की परीक्षा कराई जा रही है ताकि छात्रों को दूसरा मौका मिल सके। क्या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिला चाहने वाले छात्रों को दूसरा मौका मिलेगा?

एक्शन मोड में क्यों दिखने लगे- शिवराज, कमल और कैलाश

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और सतपुड़ा सुंदरी पचमढ़ी की सुरम्य वादियों में दो दिन अपने मंत्रि-मंडलीय सहयोगियों के साथ चिंतन कर 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए एक ऐसा मंत्र तलाशेंगे जिसके सहारे प्रदेश फिर से भाजपा के अजेय गढ़ में तब्दील हो जाए जो कि 2018 में मामूली अन्तर से ढह गया था। पचमढ़ी में चिंतन-मनन के बाद निश्चित तौर पर शिवराज कुछ और नवाचार करेंगे तथा इस बार उनका सारा ध्यान इस बात पर रहेगा कि हरिजनों, आदिवासियों, महिलाओं व समाज के कमजोर वर्गों सहित जिस भी वर्ग के लिए योजनायें बनाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन धरातल पर हो और इसमें किसी भी तरह की कोताही वे सहन करने वाले नहीं है। मंथन के बाद शिवराज एक ऐसे रुप में नजर आयेंगे जो माफियाओं, अपराधियों, निहित स्वार्थी तत्वों पर कहर बनकर टूटेंगे और इसमें आड़े आने वाली नौकरशाही को भी सहन नहीं करेंगे। अपने कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर अपने नागरिक अभिनंदन के अवसर पर उन्होंने दो-टूक शब्दों में कहा कि राज्य शासन के ऊपर कोई दबंग नहीं जा सकता और उसे कुचल देंगे। अपनी तथा कमलनाथ की कांग्रेस सरकार का अन्तर स्पष्ट करते हुए शिवराज का कहना है कि हमारी सरकार मिशन की सरकार है और कमलनाथ की सरकार कमीशन की सरकार थी। दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की चर्चा करते हुए बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब सडक में गड्ढा था या गड्ढे में सडक समझ में ही नहीं आता था, बिजली आती ही नहीं थी यह आम बाती थी, आज दो घंटे के लिए बिजली चली जाए तो वह बड़ी खबर बन जाती है। कमलनाथ दादा तो पैसे छोडकर ही नहीं गये थे लेकिन चाह होती है वहां राह निकालनी पड़ती है और हमने गरीबों को सुविधा देने में पैसों की कमी नहीं आने दी। शिवराज चाहते हैं कि हितग्राहियों का एक ऐसा वर्ग बने जो यह महसूस करे कि सरकार उनके लिए काफी कुछ कर रही है और क्रियान्वयन इस ढंग से हो कि लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली जो योजनायें है उससे न केवल वे लाभान्वित हों बल्कि भाजपा के लिए एक मजबूत वोट बैंक भी तैयार हो। राज्य में कांग्रेस एवं भाजपा के बीच मत प्रतिशत का बहुत बारीक-सा अन्तर है और इसी अन्तर को बढ़ाकर भाजपा का मत प्रतिशत किस प्रकार 51 प्रतिशत किया जाए वही इस चिंतन का केंद्रीय बिन्दु होगा। भांजे-भांजियों के मामा के रुप में सामाजिक रिश्ते जोडने वाले शिवराज की छवि अब एक सख्त प्रषासक के रुप में उभर रही है तथा मामा से लेकर अब उनकी छवि बुलडा. ंजर मामा की गढ़ी जा रही है, जिसकी शुरुआत राजधानी भोपाल के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रारंभ कर दी है। शिवराज सिंह चौहान के पुनः मध्यप्रदेश की कमान संभालने के बाद दो साल पूरे हो गये हैं और इसके साथ ही उनके पुराने कार्यकाल को मिलाकर वह भाजपा के सबसे लम्बे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकार्ड बना चुके हैं। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही कोरोना महामारी की चपेट में देश के साथ ही प्रदेश भी आ गया था और यह समय उनके नेतृत्व के लिए परीक्षा की घड़ी था जिसका उन्होंने सफलतापूर्वक सामना किया और ऐसे कोई हालात पैदा नहीं हुए जैसी दुश्वारियां अन्य राज्यों में देखी गयीं। न तो आक्सी. जन की कमी हुई और न ही मरीजों में किसी प्रकार की अफरा-तफरी थी। दवाइयां और इंजेक्शन का भी समय रहते प्रबंध किया गया। लेकिन इस अवधि में भी उन्होंने विकास की गति अवरुद्ध नहीं होने दी। शिवराज सरकार ने पिछले दो वर्षों में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता किसानों को दी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के तहत 10 लाख से अधिक आवास बनाये गये। केन-बेतवा लिंक परियोजना जिससे 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर में सिंचाई होगी और अटल प्रगति पथ 313 किलोमीटर की योजनायें स्व. ीकृत हुईं। ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा महिला स्व-सहायता समूहों के लगभग 9 लाख सदस्यों को आर्थिक गतिविधियों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरित किये गये। इसी अवधि में 8 हजार 276 करोड़ रुपये की लागत से 5 हजार 322 किमी लम्बी सडकों का निर्माण भी हुआ। अपने इस दो साल के कार्यकाल में शिवराज काफी बदले-बदले नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपनी छवि एक सख्त प्रशासक की गढ़ ली है और अब जहां एक और नौकरशाही को भी नियंत्रित कर रहे हैं तो वहीं माफियाओं के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति अपना रखी है और उन्हें नेस्तनाबूद करने की दिशा में कदम उठाते हुए 21 हजार एकड़ से अधिक शासकीय भूमि अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई है।

कमलनाथ की नजर में शिवराज के दो साल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ की नजर में शिवराज सरकार के दो वर्षों में प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढने की बजाय हर दृष्टि से पीछे ही गया है। कमलनाथ का आरोप है कि इस अवधि में किसी वर्ग का भला नहीं हुआ बल्कि हर वर्ग परेशान ही हुआ है। इन दो वर्षों में सिर्फ इवेन्ट आयोजनों के नाम पर जनता को गुमराह करने का काम जमकर हुआ है। उनका आरोप है कि उनकी सरकार के जाते और शिवराज सरकार के आते हमने प्रदेश में कोरोना काल में सरकार का कुप्रबंधन देखा है कि किस प्रकार हजारों लोगों की इलाज, बेड, अस्पताल, आक्सीजन, जीवन रक्षक दवाइयों के अभाव में मौतें हुई हैं। कोरोना के संकटकाल में भी सरकार लोगों को बचाने की बजाय सत्याग्रह पर बैठने, रथ पर सवार होकर घूमने, गोले बनाने जैसे इवेन्ट करती नजर आई है। सबसे ज्यादा परेशान किसान हुआ है और उसे अभी तक अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिल सका है, और यदि कुछ मिला है तो तो फिर केवल कोरे आश्वासन और भाषण।

और यह भी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि मध्यप्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा जायेगा। पार्टी ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है अभी तो उन्हीं का चेहरा है और वे अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी में बुलडोजर बाबा के रूप में योगी आदित्यनाथ की ख्याति के बाद शिवराज को बुलडा. ंजर मामा प्रोजेक्ट किए जाने के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि मध्यप्रदेश में काफी पहले से बुलडोजर चल रहा है।

ब्यूटी टिप्स : सर्दियों में फेस वाश करते समय नहीं करनी चाहिए ये गलतियां

सर्दियों में फेसवॉस करते समय हम कई गलतिया करते है जो हमारे स्किन को काफी नुकसान पहुंचाते है फेस वाश गलत तरीके से करने का तरीका स्किन लेयर्स पर असर डालता है। त्वचा की देखभाल के लिए सही से फेसवॉस उपयोग करना जरूरी है। फेसवॉश चेहरे की सफाई के लिए फायदेमंद होता है। लड़कियां स्किन केयर के लिए फेसवॉश का उपयोग रोजाना करती हैं। ठंड के मौसम में फेसवॉश से भी कई बार स्किन की सफाई ठीक से नहीं होती है। इसकी वजह कई हो सकती हैं। चेहरा धोने का तरीका और गलत फेसवॉश का इस्तेमाल सबसे प्रमुख कारण हैं। सर्दियों में स्किन की चमक बनाए रखने के लिए हम यहां पर कुछ फेसवॉश टिप्स दे रहे हैं।

– कई बार फेसवॉश लगाने का तरीका गलत होता है। कुछ लोग फेशवॉश लगाने के बाद चेहरे को रगड़ने लगते हैं। यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। फेसवॉश को चेहरे पर हल्के से लगाना चाहिए। इसके अलावा चेहरे पर फेशवॉश लगाने के बाद कुछ देर

के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे फेसवॉश का असर ठीक से होता है और स्किन की गहरी सफाई होती है।

– कई बार हमको लगता है कि फेसवॉश लग गया चेहरे की सफाई हो गयी। जबकि ऐसा नहीं होता है। चेहरे को फेसवॉश से धोने का फायदा आपको तभी मिलता है जब आप ठीक से फेसवॉश को भी चेहरे से साफ करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो फेसवॉश के कैमिकल चेहरे की स्किन को डैमेज करने लगते हैं।

– कई बार हम हर महीने एक ही तरह का फेसवॉश उपयोग करते हैं। यह स्किन केयर के लिए खराब होता है। सर्दियों में ऐसे फेसवॉश का उपयोग करना चाहिए जिसमें सैलिसिलिक एसिड और मिल्क का बेस्ड हो। अगर आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो आपको मेडिकेटेड फेसवॉश का चयन करना चाहिए।

– सर्दियों में पानी ठंडा रहता है। ऐसे में कई गलतियों की संभावना होती है। कुछ लोग गर्म पानी से चेहरा धोते हैं। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा पानी गर्म रहता है, तो चेहरे की चमक जाने लगती है। ज्यादा गर्म पानी के इस्तेमाल से चेहरे की स्किन रूखी हो जाती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको सर्दियों में गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है।

सूखे ब्रश से स्क्रब करें, किन नियमों का पालन करना है? मालूम करें

नहाते समय स्क्रब करना लेकिन त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और अगर इस स्क्रब को 'ड्राई ब्रश' की मदद से किया जाए तो आपकी त्वचा की कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। टैन की समस्या दूर होती है। आपकी त्वचा कोमल, कोमल होगी। सिर्फ अंगों को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को स्क्रब करने की जरूरत होती है। आप अलग से पैक लगाकर भी अपने चेहरे को स्क्रब कर सकते हैं। और अगर आप स्क्रब करते समय थोड़े से जैतून के तेल का उपयोग कर सकते हैं, तो आपकी त्वचा बहुत कोमल और कोमल हो जाएगी।

ड्राई ब्रश स्क्रबिंग के क्या फायदे हैं?

1. त्वचा को एक्सफोलिएट करें–चमक तभी वापस आएगी जब आपकी त्वचा की मृत कोशिकाएं हट जाएंगी। इसलिए सूखे ब्रश से स्क्रब करने से आपकी त्वचा एक्सफोलिएट हो जाती है। यानी मृत कोशिकाओं को हटा दिया जाता है। यह त्वचा की चमक को पुनर्स्थापित करता है।

2. ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है–सूखे ब्रश से स्क्रब करने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे त्वचा अच्छी रहती है। तरह–तरह की परेशानियां दूर होती हैं।

3. त्वचा पर जमा अतिरिक्त तेल और अन्य अशुद्धियों को स्क्रब करके हटाया जा सकता है। हालांकि, ऐसे में हल्के हैंड ब्रश का इस्तेमाल करें। जोर से रगड़ने से त्वचा को नुकसान होगा। त्वचा खुरदरी हो सकती है।

स्क्रब करने के बाद क्या करें?

1. त्वचा को मॉइस्चराइज करना सुनिश्चित करें। नहाने से पहले स्क्रब करें। और नहाने के बाद क्रीम लगाएं। त्वचा को मॉइस्चराइजर की बहुत जरूरत होती है। नहीं तो स्क्रब करने के बाद त्वचा खुरदरी और रूखी हो सकती है।

2. स्क्रब करते समय तेल का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप घर पर पैक या स्क्रबर बनाकर उसे स्क्रब करते हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा जैतून का तेल या शहद मिला सकते हैं।

3. मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें। नहीं तो त्वचा को नुकसान हो सकता है। और स्क्रब करते समय अपने हाथों से ब्रश को धीरे से त्वचा पर लगाएं। त्वचा को जोर से न रगड़ें। इससे त्वचा को नुकसान होगा।

इस समय भूलकर भी न खाएं दही, बन जाता है जहर..!!

दही सेहत के लिये बेहद फायदेमंद होता है। लेकिन यदि इसे गलत समय पर खाया तो ये जहर बन सकता है। आयुर्वेद पद्धति के मुताबिक दही को रात को खाने से बचना चाहिये। दरअसल रात के वक्त हमारे शरीर में कफ की प्राकृतिक प्रबलता बढ़ जाती है। इसके अलावा रात को दही खाने से पेट की बीमारी होने के भी खतरे रहते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो रात को दही खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती हैं।

दरअल रात को दही खाने से पाचन क्रिया में गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इसे पचाने के लिए एनर्जी बर्न करने की जरूरत होती है। रात के समय ज्यादातर लोग खाने के बाद सो जाते है। जिससे दिक्कत बढ़ने लगती है। इसके अलावा शरीर में यदि सूजन आदि हो तो, दही खाने से हमेशा बचना चाहिये क्योंकि यह सूजन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है।

रात के समय दही खाने से शरीर में इंफैक्शन होने का डर रहता है। इससे खांसी और जुखाम हो सकता है। वहीं, गठिया या जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो रात के समय इसका सेवन करने से परहेज करें। इससे दर्द कम होने की बजाए बढ़ जाएगा। दही टेस्ट में खट्टी, तासीर में गर्म और पचाने में भारी होती है। यह वसा, ताकत, कफ, पित्त, पाचन शक्ति बढ़ाती है। वहीं, खट्टी दही को कभी भी गरम कर के नहीं खाना चाहिये।

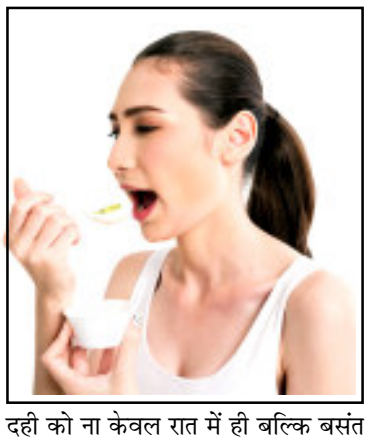

दही को ना केवल रात में ही बल्कि बसंत में भी नहीं खाना चाहिये।

अब सिर्फ 5 मिनट में डबल चिन को करें बॉय–बॉय

बिगड़ते लाइफस्टाइल के चलते आजकल लोगों में अन्य परेशानियों के साथ ही डबल चिन की समस्या भी बहुत आम हो गई है। हालांकि डबल चिन की समस्या महिला और पुरुष दोनों को होती है। लेकिन महिलाएं अपनी काया को लेकर अपेक्षाकृत ज्यादा चिंतित रहती हैं। डबल चिन वाकई पर्सनेलिटी को बुरी तरह खराब करती है। अगर आप भी डबल चिन की परेशानी से जूझ रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको इस समस्या से सिर्फ 5 मिनट में छुटकारा पाने की आसान टिप्स बता रहे हैं।

गले और आंखों का मेकअप

ये तो आप जानती ही होंगी कि आज के समय में मेकअप कुछ भी कर सकता है। यानि कि आपको अपनी शारीरिक संरचना को बदलते के लिए अब किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना पड़ता है। बल्कि मेकअप के जरिए आप जो चाहे वो आसानी से कर सकती हैं। ऐसे में अब आप खुद ही सोचिए कि डबल चिन की समस्या कितनी छोटी है? अगर आप डबल चिन से तुरंत राहत पाना चाहते हैं तो मेकअप करते वक्त थोड़ा ध्यान दें। मेकअप करते समय गले और आंखों के मेकअप पर ज्यादा ध्यान दें ताकि यह अंग उभरे हुए लगें। ऐसा करने से

लोगों का ध्यान आपकी चिन से हट जाएगा और आपका चेहरा सुंदर दिखेगा।

चेहरे की जॉ लाइन

जब हम मेकअप करते हैं तो बहुत बारीक चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जिसमें चेहरे की जॉ लाइन भी एक है। डबल चिन वाले लोगों को जॉ लाइन मेकअप पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। मेकअप के जरिए यदि आप अपनी जॉ लाइन को डार्क और उभरा हुआ करते हैं तो आप एक सीमित समय तक डबल चिन से छुटकारा पा सकते हैं।

जूलरी का चुनाव

डबल चिन से परेशान महिलाओं के लिए जूलरी एक अच्छा और आसान विकल्प है। यानि कि हैवी जूलरी पहनकर आप डबल चिन से निजात पा सकती हैं। नेकलेस की सुंदर डिजाइन या फिर सोने के तारों से बनी चेन लोगों का डबल चिन से ध्यान हटाने का अच्छा काम करती है।

कपड़ों का करें सही चुनाव

कपड़े हमारी पर्सनेलिटी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। हम जैसे कपड़े पहनते हैं वैसी ही लोगों को हमारी पर्सनेलिटी के बारे में पता चलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कपढड़ों के चुनाव से काफी हद तक हमारी मानसिकता का भी पता चलता है। कपड़ों की डिजाइन से आप डबल चिन की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। नेकलाइन, चौड़ा गला और वी–नेक डबल चिन को छिपाने में कारगर साबित होते हैं।

मीट और अण्डे से भी ज्यादा शक्तिशाली है मूंगफली, जानें कैसे?

मीट और अण्डे को सेहत बनाने और प्रोटीन लेने का सबसे अच्छा स्त्रोत कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने वजन या उम्र के हिसाब से कमजोर होता है या फिर किसी इंसान में कमजोरी होने लगती है तो उसे मीट और अण्डे खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं मूंगफली में मीट और अण्डे के मुकाबले कई गुना अधिक प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं? मूंगफली को सेहत का खजाना भी कहा जाता है। शायद आपको इस बार यकीन ना आए, लेकिन ये सच है कि मूंगफली मीट और अण्डे की तुलना में काफी शक्तिशाली होती है। आइए जानते हैं कि मूंगफली में ऐसे कौन से गुण हैं जिससे उसने मांस को भी पीछे छोड़ दिया है।

वानस्पति प्रोटीन का स्त्रोत है मूंगफली।

मूंगफली में मांस की तुलना में 2.3 गुना और अण्डे की तुलना 2.5 गुना और फलों की तुलना में 7 गुना अधिक प्रोटीन होता है।

100 ग्राम कच्ची मूंगफली खाना, एक लीटर दूध पीने के बराबर होता है।

मूंगफली खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है और हमारी पाचन क्रिया दुरस्त भी होती है।

250 ग्राम भुनी हुई मूंगफली खाने से हमारे शरीर को जितने खनिज और विटामिन्स मिलते हैं उतने 250 ग्राम चिकन खाने से भी नहीं मिलते हैं।

मूंगफली में न्यट्रीशन्स, मिनिरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं।

मूंगफली हमारे खराब कोलेस्ट्राल को अच्छे कोलेस्ट्राल में बदलती है।

मूंगफली में जितना प्रोटीन और एनर्जी होती है उतनी अण्डे में भी नहीं होती है।

मूंगफली में पाया जाने वाला प्रोटीन दूध से मिलता है और चिकनाई घी से मिलती है।

अकेली मूंगफली दूध, घी और बादाम की कमी को पूरा कर देती है।

इसे गरीब का बादाम कहा जाता है। मूंगफली खाने से शरीर गर्म रहता है और फेफड़ों को बल मिलता है।

खाने के बाद इसका सेवन करने से पाचन तंत्र अच्छा होता है और मोटापा कमजोर इंसान हेल्दी होता है।

श्वास के मरीजों के लिए भी मूंगफली खाना फायदेमंद होता है।

मूंगफली गर्म होती है इसलिए जिन लोगों को गर्म चीज खाने से परेशानी होती है वो इसका कम सेवन करें।

नीति आयोग टीम के स्वागत में उत्तराखण्ड की प्रगति पर प्रस्तुतिकरण, मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने पर दिया जोर

देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय स्थित अपने सभागार में उत्तराखण्ड दौरे पर आए नीति आयोग के सदस्य डॉ. एम. श्रीनिवास एवं उनकी टीम का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। बैठक के दौरान राज्य की ओर से प्रमुख

सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने राज्य की प्रगति एवं सलाहकार एवं कार्यक्रम निदेशक नीति आयोग डॉ. सोनिया पंत ने प्रदेश की मुख्य उपलब्धियों और आर्थिक रूपरेखा पर प्रस्तुतिकरण दिया।

मुख्य सचिव ने सदस्य नीति आयोग एवं उनकी टीम का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड ने राज्य गठन के बाद आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पर्यटन और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड कई संकेतकों पर अग्रणी राज्यों में से एक के रूप में उभरा है। राज्य ने सतत् विकास लक्ष्य इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष रैंक हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल बनाने एवं नागरिक-अनुकूल नियामक प्रक्रियाओं के जरिए जीवन-यापन को आसान बनाने की दिशा में कार्य हुआ है।

मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में दूर-दराज के क्षेत्रों में किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एक चुनौती बनी हुई है। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण को दूर करने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने में नीति आयोग से लगातार और असरदार तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है। हिमालयी क्षेत्र में स्वास्थ्य से जुड़ी क्षेत्रीय समस्याओं, क्लिनिकल बेस्ट प्रैक्टिस, क्षमता निर्माण, टेलीमेडिसिन और आपातकालीन देखभाल पर स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए एम्स और ऐसे ही अन्य सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को नॉलेज पार्टनर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

सदस्य नीति आयोग डॉ. एम. श्रीनिवास ने कहा कि उत्तराखण्ड विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से जुड़े आउटकम इंडीकेटर्स और एसडीजी लक्ष्यों पर और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उत्तराखण्ड की स्थिति मातृ मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर आदि में राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, परन्तु इनमें और सुधार की आवश्यकता है। इसके साथ ही इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और टीबी ट्रीटमेंट की दिशा में प्रयास बढ़ाए जाने पर जोर देते हुए उन्होंने प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं और आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किए जाने की बात कही। कहा कि आपातकालीन और ट्रॉमा देखभाल सेवाओं को मजबूत बनाया जाए। इसके साथ ही आयुष को मजबूत करते हुए, आयुष ईकोसिस्टम विकसित किए जाने की बात कही।

अब दो अनशनकारियों की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में किए भर्ती

चमोली। राजकीय इंटर कॉलेज नंदानगर में विज्ञान विषय शुरू कराने की मांग के लिए ग्रामीणों का अनशन लगातार जारी है। अब बुधवार को अनशन पर बैठे दो लोगों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अब उनके स्थान पर बुजुर्ग समेत दो ग्रामीण बैठ गए हैं। तहसील नंदानगर में ग्रामीणों का 25 मई से धरना चल रहा है। ग्रामीणों ने 30 जून से आमरण अनशन भी शुरू कर दिया। पहले चरण में तीन लोग अनशन पर बैठे जिसमें से दो की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनकी जगह पर दो अन्य लोग अनशन पर बैठे। मंगलवार को 30 जून से अनशन कर रहे जसपाल सिंह की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सीएचसी नंदानगर में भर्ती कर दिया गया जबकि दो अन्य प्रकाश सिंह और सुंदरी राम डटे रहे। बुधवार सुबह चिकित्सकों ने उनके स्वास्थ्य की जांच की लेकिन कुछ देर बाद दोनों की तबीयत काफी खराब होने लग गई।

राम मंदिर और बदरीनाथ मंदिर में चोरी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

नई टिहरी। अयोध्या में राम मंदिर और बदरीनाथ मंदिर में चंदा चोरी के विरोध में कांग्रेस ने घनसाली में प्रदर्शन कर धरना दिया। उन्होंने मंदिर से चढ़ावे और सोने की कथित चोरी की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।घनसाली में हनुमान मंदिर के समीप कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने कहा कि मामले को दबाने के लिए कुछ छोटे लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कहा भाजपा के राज में मंदिरों में चोरी की घटनाओं से श्रद्धालु आहत हैं। मंदिरों में हुई चोरियां कोई छोटी घटना नहीं है, यह डकैती है। इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुंदर लाल उनियाल, जसवीर नेगी, शंकरपाल सजवाण, लक्ष्मी प्रसाद जोशी, दिनेश लाल, दिनेश पैन्यूली, राम सिंह, बालकृष्ण नौटियाल आदि मौजूद रहे। दूसरी ओर, घनसाली के विधायक शक्ति लाल शाह और दायित्वधारी विनोद सुयाल ने कांग्रेस के प्रदर्शन को नौटंकी बताया। कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के जनता को चोरी के नाम पर भ्रमित करने की कोशिश कर रही है।

बांधों से पानी छोड़ने पर प्रभाव भी बताना होगा

देहरादून। राज्य के सभी प्रमुख बांधों एवं बैराजों को प्रतिदिन सुबह 8 बजे तथा शाम 8 बजे अपने जलाशयों के जलस्तर, इनफ्लो, आउटफ्लो तथा डिस्चार्ज से संबंधित अद्यतन जानकारी अनिवार्य रूप से यूएसडीएमए को उपलब्ध करानी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बुधवार को यूएसडीएमए स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में संबंधित विभागों एवं जल विद्युत परियोजनाओं के अधिकारियों को मानसून के दौरान बेहतर समन्वय तथा निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी भी बांध अथवा बैराज से पानी छोड़ा जाना प्रस्तावित हो तो इसकी पूर्व सूचना राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र तथा संबंधित जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। सूचना में यह भी उल्लेख किया जाए कि छोड़ा गया पानी कितने समय में किन-किन क्षेत्रों तक पहुंचेगा, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में नदी के जलस्तर में कितनी वृद्धि होने की संभावना है तथा इससे संभावित प्रभाव क्या होंगे ताकि समय रहते संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा सकें।

सचिव सुमन ने सभी परियोजनाओं को निर्देशित किया कि पूर्व चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत स्थापित नदी जलस्तर सेंसरों एवं डिस्चार्ज मॉनिटरिंग सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों को एपीआई के माध्यम से रियल टाइम में यूएसडीएमए के साथ साझा किया जाए। बैठक में सभी जल विद्युत परियोजनाओं एवं बांध प्रबंधन को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थापित ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन तथा अर्ली वार्निंग सिस्टम का विस्तार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विशेष रूप से टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन को अपने क्षेत्र में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 25 करने के निर्देश दिए ताकि मौसम संबंधी आंकड़े अधिक सटीक एवं व्यापक रूप से उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने कहा कि एक ही नदी तंत्र में स्थित अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम बांधों तथा बैराजों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। सभी परियोजनाएं आपस में नियमित रूप से जलस्तर, वर्षा, डिस्चार्ज तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान-प्रदान करें, जिससे किसी भी आकस्मिक स्थिति में समन्वित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी-प्रशासन प्रकाश चंद्र ने कहा कि सभी परियोजनाओं में स्थापित डिस्चार्ज सायरन, चेतावनी उपकरणों तथा विभिन्न सेंसरों की नियमित टेस्टिंग की जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये पूरी क्षमता के साथ कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान तकनीकी उपकरणों की कार्यशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए किसी भी प्रकार की तकनीकी कमी को तत्काल दूर किया जाए।

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा ने कहा कि बाढ़ संभावित एवं संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक मशीनरी एवं उपकरणों की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित की जाए। जल निकासी व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए तथा ऐसी सभी व्यवस्थाएं पहले से तैयार रखी जाएं, जिनसे भारी वर्षा के दौरान आबादी वाले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न होने पाए।

बैठक में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी-प्रशासन प्रकाश चंद्र, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा, सिंचाई विभाग, यूजेवीएनएल, केन्द्रीय जल आयोग, टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी जोशीमठ, एनएचपीसी टनकपुर एवं धौलीगंगा, जीवीके अलकनंदा परियोजना, जेपी ग्रुप विष्णुप्रयाग तथा मौसम विज्ञान केन्द्र देहरादून के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई चारधाम परियोजना के पैकेज २ एवं पैकेज ३ से संबंधित बैठक

देहरादून(। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रमेश कुमार सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में चारधाम परियोजना के पैकेज 2 एवं पैकेज 3 से संबंधित बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (छभ्प्क्ब्स्) द्वारा चारधाम परियोजना के पैकेज 2 एवं पैकेज 3 से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण मुआवजा वितरण, बस। स्तर पर लंबित मुआवजा वितरण, मध्यस्थता वादों, स्वामित्व विवादों तथा अन्य प्रासंगिक विषयों की वर्तमान स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया।

प्रमुख सचिव ने चारधाम परियोजना के पैकेज 2 एवं पैकेज-3 के अन्तर्गत लंबित भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए सम्बन्धित भूमि का कब्जा कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (छभ्प्क्ब्स्) को अधिकतम एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने कहा कि निधरित समयावधि के भीतर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण न किए जाने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी

स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक **गार्गी मिश्रा** द्वारा इंटर ग्राफिक आर्फसेट प्रिंटर्श 64 नेशविला रोड़ देहरादून, उत्तराखंड से मुद्रित, 98, 2-फ्लोर, सनशाइन अपार्टमेन्ट, नागल हटनाला, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून - 248001 से प्रकाशित।

सम्पादकः
गार्गी मिश्रा
8765441328

समस्त विवाद देहरादून न्यायालय के अधीन होंगे।